शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार
मध्यप्रदेश

अब ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस भी मिलेंगे

विभाग का प्रस्ताव तैयार, हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था

भास्कर ब्यूरो | भोपाल

प्रदेश में ड्राइविंग स्कूल वाहन की ट्रेनिंग के साथ ही लायसेंस भी बना कर देंगे। परिवहन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पहले जिलों में पीपीपी मोड पर ड्राइविंग स्कूल खोलने जाने की योजना थी लेकिन अब इस स्कूलों को लाइसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही मुख्यमंत्री की अनुमति ली जायेगी। हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। इधर विभागीय सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है, अब केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है।

शिवराज की योजना का नाथ सरकार में बना था प्रस्ताव

2018 के पूर्व शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस इस व्यवस्था को लेकर योजना बनाने का विचार किया गया था। बाद में अस्तित्व में आई कमलनाथ सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि नाथ सरकार को गिराकर शिवराज सरकार एक बार फिर अस्तित्व में आई है ऐसे में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को अपडेट कर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यहां बता दें कि कमलनाथ और शिवराज दोनों के ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहें है।

दो एकड़ जमीन पर दो करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

ड्राइविंग स्कूल का प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए दो एकड़ जमीन की आनिवार्यता रखी गई है। लगभग दो करोड़ के इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सीडी दी जायेगी। ऐसे में इंवेस्टर को केवल एक करोड़ की लागत लगानी होगी, शेष एक करोड़ की सरकार द्वारा सब्सीडी मिलेगी। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के किसी भी जिले में लगाया जा सकेगा।

ड्राइविंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में एक नई व्यवस्था एड की गई है। ड्राइविंग स्कूलों को अब लायसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने का प्रावधान किया जाना है। स्वीकृति मिलते ही व्यवस्था लागू की जायेगी। इस प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत सब्सीडी भी देने का प्रावधान है।

एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, मप्र परिवहन

एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु [raghu@dbcorp.in]

विश्वास बुरे दौर में अच्छा देखने में मदद करता है

'जय सीरम'। यह कम से कम आज तो अभिवादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है! 16 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज होने को तैयार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 3,006 टीकाकरण केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। कम से कम आज से हम सभी अपने मोबाइल फोन मैसेजों को गर्व की नजर से देखेंगे (जब उनमें उन लोगों की संख्या दिखेगी, जिन्हें टीका लग चुका है)। यह नजर उस नुकसान वाली नजर (कितनी मौतें हुईं) से पूरी तरह अलग होगी, जिससे हम अब तक मोबाइल पर दुनिया देख रहे थे। इसलिए 'सीरम' को 'जय' कहना तार्किक है, क्योंकि यह हमारे नजरिए को बदल देगा, जिससे अब हम अपनी नई दुनिया को देखेंगे। जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, मुझे यकीन है कि कोविड-19 हमारे लिए बीते कल की बात हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने कोरोना के दिनों में कुछ सकारात्मक नहीं सीखा। जिन लोगों को विश्वास था कि बुरे दिनों में भी कुछ अच्छा है, उन्होंने काम करने के नए तरीके और समय से आगे रहने की योजना बनाने जैसी कई चीजें सीखीं।

आपको डांस कपल वीपी और शांता धननजयन याद हैं, जो 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और कुछ साल पहले मोबाइल फोन विज्ञापनों में दिखे थे, जिनमें वे गोवा की यात्रा पर अकेले जाते हैं और अपनी टैटू वाली फोटो समेत कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल साइट्स पर अपलोड करते हैं? वे दरअसल अपने उम्रवर्ग के लोगों में जीवन के आनंद के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाने का प्रचार कर रहे थे। इस उम्र में, जब उनकी दैनिक डांस क्लास लॉकडाउन में बंद हो गईं, तब धननजयन दंपती ने दो प्रस्तुतियां तैयार कीं और ऑनलाइन माध्यम अपनाकर अपनी नई शैलियों में न सिर्फ शहर के, बल्कि दुनियाभर के छात्रों तक पहुंचे। उनके मुताबिक ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक को आमने-सामने की कक्षा की तुलना में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। आज विज्ञापन वाले ये दंपती ऑनलाइन क्लास से दुनियाभर में ज्यादा मशहूर हो गए हैं। एक अन्य उदाहरण देखें। लॉकडाउन के दौरान वन अधिकारियों की जगह काम करने वाले सेवानिवृत्त तलाठी (पटवारी) याकूब कोठारिया ने अहमदाबाद के पास ढांढुका में रोजका गांव के लोगों के साथ मिलकर कब्रिस्तान की बंजर जमीन पर 2,000 पेड़ लगाए हैं। उन्होंने 10 लाख रुपए भी दान दिए, जिन्हें तालाब बनाने, उपकरण खरीदने और उस जगह को छोटे जंगल में बदलने में खर्च किया गया। आज किसी को कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल खरीदने की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान में ही पर्याप्त फूल लगे हैं।

एक और उदाहरण सुनीता गांधी का है, जो केवल 30 घंटे में बच्चों को कुछ साक्षर बनाती हैं। सुनीता लखनऊ में शिक्षाविद् हैं और ज्यादातर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पिछले पांच साल से मुफ्त में पढ़ा रही हैं। उनका 'ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट' पूरी तरह स्वयंसेवकों से चलता है। यह इस आसान सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों से पूछिए, वे क्या जानते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़िए। सभी छात्रों के लिए एक ही तरीके की जगह,वे प्रत्येक छात्र के मुताबिक चीजें तैयार करते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में तस्वीरों और ध्वनि संकेतों से हर छात्र को शब्दों को पहचानना सिखाया जाता है। टूलकिट में 30 पाठ, 60 शॉर्ट वीडियो, किताबें, अल्फाबेट कटआउट और स्टेशनरी सामग्री हैं। **फंडा यह है कि** जिंदगी उतार-चढ़ाव भरा सफर है और केवल बुरे में अच्छा देखने का विश्वास ही आपको विजेता बनाता है।

पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट में एमपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को नियत की गई है।

यह याचिका सामाजिक संगठन अपाक्स, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ट्रांसफर करने का प्रावधान है, लेकिन पीएससी ने आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट में अंक अधिक होने के बाद भी उन्हें उनके ही वर्ग में रखा गया है। इसकी वजह से अनारक्षित और ओबीसी की कट ऑफ मार्क्स १४६-१४६ है। याचिका में कहा गया है कि सिविल सेवा नियम २०१५ में किए गए संशोधन को १७ फरवरी २०१९ से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू किए जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में लोक सेवा आरक्षण नियम १९९४ की धारा ४ की उपधारा (४) को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा

कोटा में कोचिंग उद्योग फिर से शुरू होने के लिए तैयार

कोटा (राजस्थान)। स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों को कुछ पाबंदियों के साथ फिर से खोलने की राजस्थान सरकार की मंजूरी के बाद कोटा में कोचिंग संस्थान 18 जनवरी से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। स्कूल एवं कोचिंग कोरोना के चलते लगभग 10 महीने से बंद थे। हर साल देशभर से आने वाले लगभग 1.50 लाख छात्रों के लिए कोटा शहर में कम से कम 10 बड़े कोचिंग संस्थान एवं 50 अन्य संस्थान हैं। साथ ही इस शहर में लगभग 25,000 पेइंग गेस्ट (पीजी) और 3,000 हॉस्टल हैं। इनसे हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है।

वाट्सएप वेब यूजर्स के नंबर गूगल सर्च में लीक

स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजाहरिया ने किया खुलासा

एजेंसी | नई दिल्ली

वाट्सएप में डेटा लीक का एक और मामला सामने आया है। वाट्सएप वेब यूजर्स के नंबर गूगल सर्च पर इंडेक्सिंग में मिले हैं। वाट्सएप वैसे तो मोबाइल एप है। लेकिन इसे वाट्सएप वेब के माध्यम से डेस्कटॉप और लैपटॉप पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देश में 40 करोड़ वाट्सएप यूजर हैं। वाट्सएप इस समय अपनी निजता आठ फरवरी के बाद जारी रखना है तो इसे स्वीकार करना होगा। स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजाहरिया ने शुक्रवार को गूगल सर्च पर वाट्सएप यूजर्स के निजी मोबाइल नंबर दिखाए। इसके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नंबर व्यक्तिगत हैं, न कि बिजनेस क्लास के। हाल में वाट्सएप की चैट की लिंक गूगल सर्च पर उपलब्ध होने और डेटा लीक के बाद वाट्सएप ने कहा था कि उसने गूगल से इस प्रकार की चैट की इंडेक्सिंग न करने को कहा है। इसके कारण कोई भी निजी चैट ग्रुप से जुड़ सकता है। उसने यूजर

गणवेश के लिए छात्रों को करना होगा 1 माह इंतजार

निगरानी के लिए गठित किए गए दल

भास्कर न्यूज | सतना

स्कूल शिक्षा विभाग की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के तहत अभी तक छात्रों को गणवेश का वितरित नहीं की जा सका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को फरवरी के अंत तक राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन द्वारा तैयार किए जा रहे गणवेश वितरित किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि शासन के आदेशानुशार इस बार गणवेश बनाने की जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन में पंजीकृत स्व-सहायता समूह को दी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गणवेश तैयार करने के लिए 80 प्रतिशत राशि आवंटित भी कर दी गई है।

राशि मिलने के बाद जिले के सभी स्व-सहायता समूहों द्वारा गणवेश बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह गणवेश जिला पंचायत सीईओ द्वारा गठित टीम की निगरानी में कराया जा रहा है।

जिले में ऐसे 1 लाख 78 हजार विद्यार्थी

जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 1 लाख 78 हजार छात्रों को गणवेश का वितरण किया जाना है। प्रत्येक छात्र को दो सेट ड्रेस दी जानी है। बताया गया कि प्रति छात्र 6 सौ रूपए के मान से राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन को दी गई है। फिलहाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 80 प्रतिशत राशि 85 लाख रूपए दे दी गई है। बताया गया कि पहले ही शिक्षा समिति द्वारा ड्रेस के कलर का निर्धारण कर दिया गया है।

स्व-सहायता समूह करेंगे पोषण आहार का वितरण

भास्कर न्यूज | सतना

महिला एवं बाल विकास कार्यालय ने कोटर नगर पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार पहुंचाने के लिए चार स्व-सहायता समूहों को काम दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 3 स्व सहायता समूह चार-चार और एक समूह तीन आंगनबाड़ी केन्द्र में वितरण का कार्य करेगा। जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, कृषक महिला स्व-सहायता समूह और दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा कोटर नगर पंचायत की चार-चार आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषण आहार का वितरण करेगा। जबकि शिव महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा तीन आंगनबाड़ी केन्द्र में किया जाएगा। महिला बाल विकास अधिकारी ने कहा है कि उक्त कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

एजुकेशन भास्कर

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा यह भास्कर प्रश्न बैंक

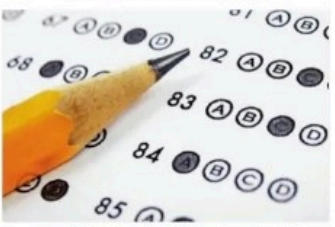

लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एजुकेशन भास्कर में इस प्रकार के प्रश्न प्रकाशित जाते हैं, जिसमें सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल-जवाब आपकी मदद करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर से आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं।

1. जापान ने भारत को कितना लोन देने की सहमति प्रदान की है?
(अ) 50 बिलियन डॉलर (ब) 45 बिलियन डॉलर
(स) 60 बिलियन डॉलर (द) 55 बिलियन डॉलर

2. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
(अ) दिल्ली (ब) मुम्बई
(स) चेन्नई (द) हैदराबाद

3. लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा?
(अ) नो योर कंट्री (ब) नो योर कॉन्स्टीट्यूशन
(स) नो योर विलेज (द) नो योर फैमिली

4. तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाला ____ राज्य बन गया है।
(अ) पहला (ब) तीसरा (स) पांचवां (द) सातवां

5. इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन (आईएसआई) की स्थापना कब की गई थी?
(अ) 1948 (ब) 1947 (स) 1946 (द) 1945

6. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) कहां है?
(अ) स्विटजरलैंड (ब) पेरिस
(स) न्यूयार्क (द) जेनेवा

7. व्यापार नीति की अंतिम समीक्षा कब की गई थी?
(अ) 2011 (ब) 2015 (स) 2013 (द) 2014

8. निम्नलिखित में NCAVES इंडिया फोरम में भाग लेने वाले देश कौन से हैं?
(अ) चीन (ब) ब्राजील (स) मैक्सिको (द) सभी

9. व्यौहार राजेंद्र सिंह के ----- जन्म दिन पर हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में तय किया गया था।
(अ) 50वें (ब) 75वें (स) 100वें (द) 101वें

10. निम्नलिखित में से कौन से देश हिंदी भाषा बोलते हैं?
(अ) पाकिस्तान (ब) नेपाल (स) मॉरिशस (द) सभी

11. भारत गृह रक्षा नीति का संबंध किससे है?
(अ) आईआरडीएआई (ब) एलआईसी
(स) अ और ब दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

12. दिल्ली स्कूल बैग पॉलिसी के अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए?
(अ) 3.5-5.5 किलो (ब) 3.5-5 किलो
(स) 3.5-4.5 किलो (द) 3.5-5.4 किलो

13. मिस्र पीने के पानी और सिंचाई की आपूर्ति के लिए _____ नील नदी पर निर्भर करता है।
(अ) 97 प्रतिशत (ब) 96 प्रतिशत
(स) 95 प्रतिशत (द) 94 प्रतिशत

14. बसवेश्वर प्रतिमा अनावरण लंदन में कब किया गया?
(अ) नवंबर 2017 (ब) नवंबर 2016
(स) नवंबर 2015 (द) नवंबर 2018

15. भारत में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्राथमिक प्रकोप की घोषणा कब की गई?
(अ) 2006 (ब) 2001 (स) 2003 (द) 2004

16. आईएमडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष गर्म वर्ष में शामिल नहीं है?
(अ) 2016 (ब) 2009 (स) 2015 (द) 2001

17. निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी विवाद में शामिल है?
(अ) इथोपिया (ब) सूडान
(स) इजिप्ट (द) सभी

18. अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
(अ) नील नदी (ब) कांगो नदी
(स) नाइजर नदी (द) नीली नील नदी

19. जीसीसी का सचिवालय कहां है?
(अ) कुवैत (ब) ओमान
(स) कतर (द) साऊदी अरब

20. त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है??
(अ) बौद्ध (ब) जैन
(स) पारसी (द) इनमें से कोई नहीं

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सहित अन्य को अवमानना नोटिस

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोकशिक्षण जयश्री कियावत, नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले और एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर की प्राचार्य विनीता पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। गाडरवारा निवासी अनिल नामदेव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसकी माँ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। सेवा के दौरान उसकी माँ का निधन हो गया, उस समय उसकी आयु 6 वर्ष थी। उसकी ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्राचार्य को आवेदन दिया गया कि जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा। 18 वर्ष होने पर उसने आवेदन किया, लेकिन उसे अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि अनावेदकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।

पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन देंगे आइआइएम

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) में प्रवेश लेने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के परिणाम जारी होने के बाद एक-एक कर आइआइएम अब अन्य प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ई-मेल कर रहे हैं। देश के शीर्ष आइआइएम अहमदाबाद से विद्यार्थियों को बुलावा आना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के कारण आइआइएम ने कैट के पैटर्न को बदल दिया था और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव की बात कही गई थी। बेहतर कैट स्कोर लाने वाले विद्यार्थियों के लिए हर बार ज्यादातर आइआइएम लिखित योग्यता परीक्षा (वॉट), ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और पर्सनल इंटरव्यू (पीआइ) लेते रहे हैं और इसके बाद प्रवेश दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार देश के कई आइआइएम सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रवेश प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले कम समय में पूरी हो जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों का चयन करने के लिए आइआइएम अन्य पैरामीटर का भी ध्यान रखता है। इसमें दसवीं, बारहवीं, ग्रेजुएशन और काम के अनुभव को भी ध्यान रखा जाता है। इससे कई बार अच्छे पर्सेंटाइल लाने वालों को भी मनपसंद आइआइएम से कॉल नहीं आते है।

घर बैठे हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू

कोरोना महामारी के कारण आइआइएम इंदौर और अन्य आइआइएम से विद्यार्थियों को अगली प्रक्रिया में शामिल होने का ई-मेल प्राप्त होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। इसे ऑनलाइन मोड से आयोजित किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा जारी एक निर्धारित वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा और इसके बाद इंटरव्यू की शुरुआत होगी। परीक्षा विशेषज्ञ आकाश सेठिया का कहना है कि आइआइएम से विद्यार्थियों को ई-मेल आना शुरू हुए हैं। कुछ दिन में ज्यादातर आइआइएम अगली प्रक्रिया के लिए ई-मेल कर देंगे। वैसे तो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही ज्यादातर आइआइएम विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं लेकिन अभी पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आई है।

जबलपुर में महाकोशल विश्वविद्यालय खोलने अध्यादेश जारी

भास्कर ब्यूरो, भोपाल | शिवराज सरकार ने जबलपुर में महाकौशल विवि खोलने राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी कर दिया है। इस निजी विवि का संचालन आरएस एजुकेशनल सोसायटी जबलपुर करेगी तथा ग्राम अंताखेड़ा चारगांव रोड पोस्ट तिलवारा जिला जबलपुर में कैम्पस होगा। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मप्र रहेगा। यह प्रदेश का चालीसवां निजी विवि होगा। इधर उन्चालीसवां निजी विवि श्री अरविन्दो यूनिवर्सिटी होगी जिसे श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेस इंदौर संचालित करेगी। इसका केम्पस इंदौर-उज्जैन हाईवे पर एमआर-10 रोड, सांवेर जिला इंदौर में रहेगा। इसका कार्यक्षेत्र भी पूरा मध्यप्रदेश रहेगा।

अब बच्चों को नहीं होगी परेशानी, सरकारी स्कूलों के लिए चलेगी बस

स्कूल शिक्षा विभाग तैयार कर रहा योजना, सीएम राइज स्कूलों पर खर्च होंगे साइकिल के तीन सौ करोड़

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण काल में स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश की स्कूली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्टीम एजुकेशन पद्धति, सीएम राइज स्कूल योजना, ऑनलाइन एजुकेशन, हमारा घर हमारा विद्यालय जैसी कई पहल के बाद अब विभाग सरकारी स्कूलों के बच्चों को दो पहिया वाहन से चार पहिया वाहन पर स्कूल लाने को लेकर तैयारी कर रहा है। यानि साइकिल योजना के बदले अब बस योजना को लेकर विभाग तैयार कर रहा है। साइकिल पर खर्च होने वाला लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सीएम राइज योजना के तहत अपडेट होने वाले स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। इन स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार बस चलाएगी। पहले चरण में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना सिर्फ सीएम राइज स्कूल के बच्चों के लिए होगी। वहीं फिलहाल शेष स्कूलों के बच्चों को साइकिल मिलेगी। नए प्रयोग के बेहतर परिणाम आने पर इसे सभी स्कूलों पर लागू किया जाएगा और साइकिल योजना बंद की जाएगी।

दो किमी दूर से आने वाले बच्चों को मिलती है साइकिल

प्रदेश में 1 लाख 42 हजार 512 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल एवं 6 हजार 534 हाईस्कूल व हायरसेकेंडरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में साइकिल वितरण के लिए लगभग 5 लाख 91 हजार 406 विद्यार्थी हैं। वर्ष-2017 से 2 किमी दूर से आने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। इस तरह सत्र 2019-20 में उन सभी विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएगी, जो 6वीं व 9वीं में अध्ययनरत हैं। इसके लिए लगभग 6 लाख साइकिलें खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले में 3874 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएगी। इस बार कक्षा छठवीं के एक लाख 58 हजार 500 और नववीं के 4 लाख 32 हजार साइकिलें दी जानी हैं।

कैसे होंगे सीएम राइज स्कूल?

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के एक लाख दो हजार सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 9200 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में अपडेट किया जाना है। प्रत्येक सीएम राइज स्कूल में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह प्रदेश भर के सीएम राइज स्कूलों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन स्कूलों में हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाई होगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्वीमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरियाए जिम, सिटिंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें प्री-नर्सरी से हायर सेकेंडरी की कक्षाएं संचालित होंगी।

इसलिए पड़ी इस प्रस्ताव की जरूरत

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लगभग 5.91 लाख बच्चों को साइकिल वितरण योजना के तहत लाभ मिलता है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राईज स्कूलों को अपडेट करने की कवायद तेज कर दी है, जिसमें बड़ी राशि खर्च होनी है, लेकिन, बताया जाता है इस सब के लिए विभाग के पास अभी पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए अधिकारियों द्वारा साइकिल योजना से बच्चों को बस से स्कूल ले जाने की यह योजना तैयार की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी विभागीय अधिकारी बोलने से बच रहे हैं।

साइकिल वितरण योजना अभी नहीं होगी बंद

अभी फिलहाल साइकिल वितरण योजना को बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम राइज योजना भी शामिल है। जिस पर काम जारी है।

रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

वरिष्ठ शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग

भोपाल। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन मंत्रालय, केंद्र सरकार के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ शिक्षकों के लिए आठ दिवसीय ऑनलाइन मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एनआईटीटीटीआर, भोपाल द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार पांडेय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए संरक्षक प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 95 वरिष्ठ शिक्षकों ने प्रतिभागिता की।

केन्द्र सरकार की नीति है कि अभिकरण के कर्मी स्थाई नहीं माने जाएंगे

डीआरडीए के 5000 कर्मचारियों को झटका

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425174141

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत रहे कर्मचारियों को एक और झटका लगा है। अभिकरण बंद करने के बाद सभी कर्मचारियों को पंचायत विभाग में विलय तो कर लिया गया है लेकिन उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। इससे प्रदेशभर के पांच हजार से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। हर कर्मचारी के हिस्से में औसतन आठ लाख रुपए आ रहे हैं जो नहीं मिलेंगे।

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत डीआरडीए में सेवारत अमले को दिसम्बर 1997 में जनपद तथा जिला पंचायत में विलय कर दिया गया था। इस संबंध में 25 सितम्बर 97 में

अधिसूचना भी जारी कर दी गई। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विकास आयुक्त कार्यालय ने डीआरडीए के कर्मचारियों को जिला और जनपद पंचायतों में रिक्त समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर दिया।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इधर, ऑल इंडिया डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर ऐसासिएशन ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाते हुए पक्ष रखा कि कर्मचारियों को विभाग में संविलियन करने के साथ उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए।

यह कहते हुए पेंशन देने किया मना

पंचायत विभाग ने कहा कि डीआरडीए के कर्मचारियों का विलय कर दिया गया है लेकिन उन्हें शासकीय सेवक नहीं माना गया है इसलिए पेंशन की पात्रता नहीं रहेगी। ग्रेच्युटी राशि भी शासन द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में डीआरडीए के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करना अथवा पेंशन का प्रावधान किया जाना संभव नहीं है।

केन्द्र के नियमों का हवाला

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2002 में जारी गाइड लाइन का हवाला देते हुए कहा है कि नीतिगत तौर पर डीआरडीए का कोई स्थायी कर्मी वर्ग नहीं होगा। अभिकरण में सीधी भर्ती करने की अनुमति भी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के रामकुमार सिंगरोले का कहना है कि प्रत्येक राज्य में अलग लाइन डिपार्टमेंट का उल्लेख है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भर्ती नियम में कृषि, उद्योग, सहकारिता, समाज कल्याण तथा योजना एवं आर्थिक सांख्यकी विभाग को लाइन डिपार्टमेंट माना है।

पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम कटघरे में

113 फीसदी आरक्षण लागू करने का आरोप, पक्ष रखने के निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर
editor@peoplessamachar.co.in

मप्र लोक सेवा आयोग-2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर मामले में आरोप है कि पीएससी ने 113 फीसदी आरक्षण लागू किया है, जो कि अवैधानिक है। मामले में मुख्य परीक्षा पर रोक लगाए जाने की राहत चाही गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में शासकीय अधिवक्ता को स्टेक्शन प्राप्त कर पक्ष रखने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है।

यह मामले अपावस संगठन सहित एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा 2019 का 21 दिसंबर को वैधानिकता सहित मप्र सिविल सेवा परीक्षा नियम 2015 के संशोधन 17 फरवरी 2020 को संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उक्त चारो केटेगिरी के आरक्षित अभ्यर्थियों के मेरिट में अंक अधिक होने के बावजूद भी उन्हें अपनी ही केटेगिरी में समाहित किया गया है, जबकि नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित में ट्रांसफर करने का प्रावधान है।

नियमों को किया दरकिनार

इसके बावजूद पीएससी ने नियमों को दरकिनार करते हुए सभी आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी ही केटेगिरी में रखा है। जिससे ओबीसी एवं अनारक्षित की कटऑफ 146-146 अंक है तथा पीएससी ने 113 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है जो अवंभित है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 40 फीसदी, ओबीसी के 27, एससी के लिए 16 व एसटी के लिए 20 व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी जिससे कुल आरक्षण 113 फीसदी हो गया है, जो कि अवैधानिक है।

ये चाही गई राहत

मामले में राहत चाही गई है कि पीएससी द्वारा ली जाने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। मामले में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग व लोक सेवा आयोग सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने पक्ष रखा।

प्री-बोर्ड के बाद पता चलेगा मुख्य परीक्षाएं लिखित होंगी या ऑनलाइन

■ माह के अंत तक आयोजित होंगे एग्जाम

स्टार समाचार | रीवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल माह के अंत में प्रारंभ होगी। मगर अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह परीक्षाएं लिखित होंगी या ऑनलाइन। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा में काफी बदलाव कर दिए गए हैं। यहां तक कि इस बार दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। एक तरह से देखा तो प्री-बोर्ड परीक्षा न सिर्फ छात्रों की तैयारी के लिए हो रही बल्कि परीक्षा का

आयोजन करने वाले मण्डल के लिए भी प्री- बोर्ड एक अभ्यास की तरह है।

अपलोड हो चुके हैं प्रश्न बैंक

बताया गया है कि बोर्ड द्वारा सेलेबस में काफी कटौती कर दी गई है। इसके अलावा प्री-बोर्ड के लिए प्रश्न बैंक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जब परीक्षाओं का आयोजन शुरू होगा तो प्रश्न पत्र के प्रिंट निकालकर छात्रों में वितरित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्री-बोर्ड परीक्षा छात्रों व शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से यह तय होगा कि बोर्ड परीक्षा की वार्षिक तैयारी कैसी होनी चाहिए और अब तक अध्ययन-अध्यापन कैसा हुआ है और इसे कैसे गुणवत्तायुक्त बनाया जा सके।

दो बार होनी है बोर्ड परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार सप्लीमेंट्री का प्रावधान समाप्त कर दिया है। जाहिर है कि इस सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है। ऐसे में जो परीक्षार्थी पहली परीक्षा में असफल रहेगा वह दूसरे राउण्ड की परीक्षा में शामिल हो सकता है। बताया गया है कि इस बार छात्रों का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा और फेल होने वाले छात्रों की मार्कशीट में स्टार नहीं लगाया जाएगा।

दोगुना होगा मूल्यांकनकर्ताओं का काम

मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का मानना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है वह भले ही छात्रहित में है मगर इससे मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का काम दोगुना हो जाएगा। आमतौर पर मूल्यांकन करने में एक माह का समय लग जाता है। मगर इस बार दो बार परीक्षाएं होनी हैं इसका मतलब है कि दो बार मूल्यांकन करना पड़ेगा। इससे मूल्यांकनकर्ताओं का काम भी दोगुना हो जाएगा।

ऐसे होगी ऑनलाइन परीक्षा

मण्डल द्वारा सत्र 2020-21 की परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पेन ड्राइव के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा केन्द्रों में प्रिंटर व फोटोकापी मशीन से विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्री-बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और विभाग का यह प्रयोग सफल हुआ तो संभवतः बोर्ड परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो सकती हैं।

वेधशाला में पढ़ाएंगे खगोल विज्ञान, अगले सत्र से डिप्लोमा भी -मंत्री परमार

जीवाजी वेधशाला में नक्षत्र वाटिका का लोकार्पण

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

शासकीय जीवाजी वेधशाला में अगले शैक्षणिक सत्र में खगोल विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह घोषणा स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने की।

वे शुक्रवार को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और स्कूल शिक्षा विभाग की अगुवाई में शासकीय जीवाजी वेधशाला में नक्षत्र वाटिका के लोकार्पण पर संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा हर इंसान को खगोलीय ज्ञान होना चाहिए। डोंगला को आईआईटी इंदौर से जोड़ा है। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा वेधशाला में वराह मिहिर की मूर्ति भी लगाई जाना चाहिए। साथ ही स्कूली बच्चों को वेधशाला, तारा मंडल, डोंगला का भ्रमण करवाएं। जिससे उन्हें खगोलीय ज्ञान मिले। विधायक पारस जैन बोले जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा जयपुर से बनवा कर वेधशाला में लगवाई है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के उपनिदेशक प्रशांत डोलस ने स्वागत भाषण दिया। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ.आरपी गुप्त ने नक्षत्र वाटिका की जानकारी दी। इस अवसर पर वेधशाला की ओर से पहली बार प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन भी किया।

नवोदय... पहले 13 को होनी थी

9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा अब 24 फरवरी को

भोपाल| नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए होने वाली जेएनवी प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीख स्थगित कर दी है। एनवीएस ने 13 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। अब नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित होगी। अभ्यर्थी नई परीक्षा तारीख को जेएनवी (जेएनवी) की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के जरिए देख सकते हैं।

आरजीपीवीवी : ओपन बुक सिस्टम की परीक्षा में डाक और ई-मेल से नहीं लेंगे उत्तर पुस्तिकाएं

भोपाल/इंदौर • राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवीवी) अंतिम दो सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर ओपन बुक सिस्टम से आयोजित करेगा, लेकिन आरजीपीवी इस बार की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को डाक या ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं करेगा। इस बार उत्तरपुस्तिका जमा करने के लिए दो तरह से सुविधा दी जाएगी। प्रश्नपत्र हल करने के बाद उत्तरपुस्तिका विवि द्वारा दिए गए लिंक पर अपलोड करनी होगी। यदि लिंक अपलोड नहीं होती है तो छात्र को आरजीपीवी से संबद्ध कॉलेज या कलेक्शन सेंटर पर संबंधित परीक्षा की तारीख में ही जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उत्तरपुस्तिका जमा नहीं की जाएगी। पिछली बार की समस्याओं को देखते हुए इस बार विवि प्रशासन ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे परीक्षा केंद्र के नजदीक रहकर ही ओपन बुक सिस्टम के तहत परीक्षा देंगे। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या व्यवधान के कारण उत्तरपुस्तिका जमा नहीं होती है तो कलेक्शन सेंटर पर ही समय सीमा में जमा कराई जा सके।

वर्तमान प्रणाली के अनुसार ही परीक्षा

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की पुरानी प्रणाली ग्रेडिंग व सीबीसीएस प्रणाली को खत्म कर दिया है। ऐसे छात्र जो इन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उन्हें परीक्षा में वर्तमान प्रणाली सीबीजीएस के अंतर्गत टाइम टेबल के अनुसार प्रश्नपत्रों का शीर्षक मिलाकर शामिल होना पड़ेगा।

स्कूल शिक्षा सचिव सहित अन्य को अवमानना नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए राज्य की स्कूल शिक्षा सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत, जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर अरुण झंगले सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। अवमानना याचिकाकर्ता गाडरवारा (नरसिंहपुर) निवासी अनिल नामदेव की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने दलील दी कि उनकी मां शासकीय स्कूल में शिक्षिका थीं। जब मां का निधन हुआ, तब उनकी आयु महज छह वर्ष थी। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य को आवेदन दिया गया था कि जब आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे। इसी आधार पर जब आयु 18 वर्ष हो गई तो उसने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दरकिनार कर दिया गया। इस पर वह हाई कोर्ट चला आया। एकलपीठ ने याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। निर्धारित समयावधि के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, अवमानना याचिका के जरिए नए सिरे से हाईकोर्ट आना पड़ा। (नप्र)

फीस फिक्स नहीं तो प्रवेश नहीं दे पाएंगे 300 कॉलेज

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (फीस कमेटी) द्वारा प्रदेश के 300 प्रोफेशनल कॉलेजों की आगामी तीन सत्रों की फीस निर्धारित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

आगामी तीन सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों को 30 अप्रैल तक प्रस्ताव करना होगा। कॉलेज अपनी फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें प्रवेश करने काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे उनका जीरो ईयर तक घोषित हो सकता है। फीस कमेटी द्वारा इस बार फीस फिक्शेसन में कई बदलाव किए गए हैं। अब कॉलेजों को गत वर्ष हुए खर्च के हिसाब से ही फीस मिलेगी। इससे उनकी फीस में काफी कटौती हो सकती है। इसका फायदा अब विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्हें मिलुने वाली सुविधाओं के हिसाब से फी ल्हो लगी। नी होगी। अभी तक प्रदेश के कॉलेज अपनी पिछली फीस और औसतन फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी को आवेदन देते थे। उनके आवेदन में कई ऐसे दस्तावेज होते थे, जिसके बिहॉफ पर कमेटी उनकी पिछली फीस या न्यूनतम फीस तय कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फीस कमेटी ने आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करने के मापदंड तैयार किए हैं। इससे कॉलेज विद्यार्थियों से मनमानी नहीं कर सकेंगे और सही फीस ही ले पाएंगे।

प्रभारी चीफ इंजीनियर वर्मा के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र मामले की जांच

भोपाल| फर्जी जाति प्रमाण-पत्र से नौकरी पाए जाने का एक और मामला राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास पहुंचा है। यह मामला जबलपुर में पदस्थ प्रभारी चीफ इंजीनियर एससी वर्मा का है। हाईकोर्ट ने छानबीन समिति से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग ने लोक निर्माण विभाग से वर्मा का जांच प्रतिवेदन मांगा है। जांच प्रमुख सचिव आदिम जाति, आयुक्त आदिम जाति कल्याण और विभागीय अधिकारी की समिति को करना है। कोर्ट में दायर याचिका में वर्मा की जाति धांगड़ बताई है, जो रायसेन जिले के भोजपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है, जबकि नौकरी पाने के दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का बनाया था। उस दौरान इस वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग का असिस्टेंट इंजीनियर का एक ही पद था, जिस पर उनकी भर्ती हुई। लोक निर्माण विभाग में ही पूर्व में अधीक्षण यंत्री (एसई) भूगांवकर के मामले की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने जांच की थी, जिसमें उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। समिति ने उन्हें बर्खास्त किए जाने की अनुशंसा की थी, लेकिन विभाग ने सिर्फ उन्हें रिवर्ट किया। भूगांवकर अधीक्षण यंत्री के पद पर थे, उन्हें दो पद नीचे रिवर्ट कर जिस पद पर वे भर्ती हुए थे असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया है, वे विभाग में फिलहाल इस पद पर पदस्थ हैं।

नर्सिंग काउंसिल का नया कारनामा... रिजल्ट में हेराफेरी के बाद अब मान्यता में भी धांधली

नर्सिंग कॉलेज को अब दी सत्र 2019-20 की मान्यता, कई छात्रों का भविष्य अधर में

भोपाल • डीबी स्टार

नर्सिंग काउंसिल में नई-नई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। रिजल्ट में हेराफेरी के बाद अब यहां कॉलेजों को मान्यता देने में भी मनमर्जी का खेल चल रहा है। आलम यह है कि सत्र 2019-20 के लिए एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता 29 दिसंबर 2020 को गुपचुप तरीके से दे दी गई है। काउंसिल की रजिस्ट्रार ने यह मान्यता ऑफलाइन जारी की है। प्रदेश भर के 451 निजी कॉलेजों में एएनएम, जीएनएम समेत अन्य कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। काउंसिल ने हर वर्ष की तरह इन कॉलेजों की नवीन मान्यता, सीटों में वृद्धि और नए कॉलेजों की मान्यता के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। यह सर्कुलर सत्र 2020-21 के लिए है। खास बात यह है कि काउंसिल ने सर्कुलर जारी करने के अगले ही दिन यानी 29 दिसंबर को डिंडोरी के जय भारती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस संस्थान को पिछले सत्र 2019-20 के लिए मान्यता प्रदान कर दी। मान्यता देने के लिए ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग न कर गुपचुप तरीके से ऑफलाइन मंजूरी दी गई।

इस मामले में डीबी स्टार ने जब कॉलेज संचालक से बात की तो पता चला कि बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के छात्रों का एडमिशन हो चुका है और ऑनलाइन पढ़ाई भी करा रहे हैं। मान्यता के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमें बेड तो पहले ही अलॉट हो गए थे। बस मान्यता बची थी तो अब वो भी मिल गई। इस मामले में प्रश्न यह उठता है कि बिना मान्यता वाले कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब परीक्षा में शामिल होने देना कितना सही है। रजिस्ट्रार सीके दिवगैया का कहना है कि यदि कॉलेज बिना मान्यता मिले छात्रों को एडमिशन देता है तो यह गलत है। ऐसे में इन छात्रों का भविष्य मुश्किल में फंस सकता है।

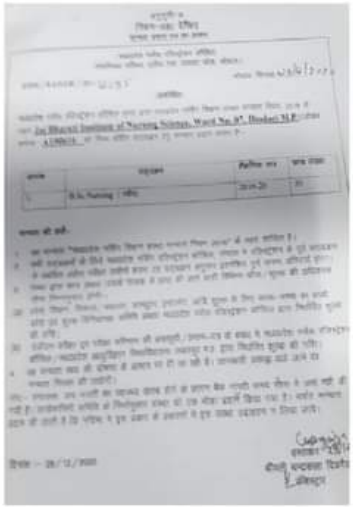

डिंडोरी के जय भारती इंस्टीट्यूट को पुराने सत्र की मान्यता ऑफलाइन जारी की गई।

नर्सिंग काउंसिल का दफ्तर।

दिनभर में पूरी कर दी जांच, गड़बड़ी के लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं

उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर और बारकोड में अदला-बदली करके पास-फेल का गोरखधंधा करने वाले कर्मचारी अभी भी काउंसिल में ही जमे हुए हैं। पहले यहां अनुपस्थित छात्रों को भी पास की मार्कशीट जारी करने के मामले उजागर हुए थे। इसके अलावा जिन कॉलेजों के रिजल्ट रोकने के लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उनके भी रिजल्ट बनाकर कॉलेजों को भेज दिए गए थे। इसी तरह की कई गड़बड़ियों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने इन मामलों की जांच दिनभर में कर ली। जांच में केवल भोजन के बिलों में मामूली गड़बड़ी पाए जाने का तर्क देते हुए आउटसोर्स कर्मचारी प्रतिभा भाटी को एग्जाम सेक्शन से हटाकर रीन्यूअल सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि तर्क ये भी है कि जिस भोजनालय से भोजन और चाय-नाश्ता आता था वह प्रतिभा के पति का है और गड़बड़ी पाए जाने के बाद लंबे समय से सेवाएं दे रहे इस भोजनालय से काउंसिल ने नाता तोड़ लिया है।

सीधी बात

बिना मान्यता एडमिशन नहीं दे सकते कॉलेज

सीके दिवगैया
रजिस्ट्रार, नर्सिंग काउंसिल

• डिंडोरी के जय भारती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस को पुराने सत्र की मान्यता किस आधार पर दी गई?

कॉलेज संचालक को हार्ट अटैक आया था और इस वजह से वह बैंक गारंटी नहीं दे पाया। दो साल मान्यता रीन्यू न हो तो फिर पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करना पड़ती।

• इस कॉलेज में तो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। बिना मान्यता बच्चों को एडमिशन देना कितना सही है।

बिना मान्यता बच्चों को एडमिशन देना पूरी तरह से गलत है। ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है।

अब ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस भी मिलेंगे

विभाग का प्रस्ताव तैयार, हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था

भास्कर ब्यूरो| भोपाल

प्रदेश में ड्राइविंग स्कूल वाहन की ट्रेनिंग के साथ ही लायसेंस भी बना कर देंगे। परिवहन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पहले जिलों में पीपीपी मोड पर ड्राइविंग स्कूल खोलने जाने की योजना थी लेकिन अब इस स्कूलों को लाइसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही मुख्यमंत्री की अनुमति ली जायेगी। हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। इधर विभागीय सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है, अब केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है।

शिवराज की योजना का नाथ सरकार में बना था प्रस्ताव

2018 के पूर्व शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस इस व्यवस्था को लेकर योजना बनाने का विचार किया गया था। बाद में अस्तित्व में आई कमलनाथ सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि नाथ सरकार को गिराकर शिवराज सरकार एक बार फिर अस्तित्व में आई है ऐसे में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को अपडेट कर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यहां बता दें कि कमलनाथ और शिवराज दोनों के ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहें है।

दो एकड़ जमीन पर दो करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

ड्राइविंग स्कूल का प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए दो एकड़ जमीन की आनिवार्यता रखी गई है। लगभग दो करोड़ के इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सीडी दी जायेगी। ऐसे में इंवेस्टर को केवल एक करोड़ की लागत लगानी होगी, शेष एक करोड़ की सरकार द्वारा सब्सीडी मिलेगी। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के किसी भी जिले में लगाया जा सकेगा।

ड्राइविंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में एक नई व्यवस्था एड की गई है। ड्राइविंग स्कूलों को अब लायसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने का प्रावधान किया जाना है। स्वीकृति मिलते ही व्यवस्था लागू की जायेगी। इस प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत सब्सीडी भी देने का प्रावधान है।

एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, मप्र परिवहन

उच्च पद भार नीति में शिक्षक संवर्ग को शामिल करेगी समिति

भोपाल। प्रदेश में सरकारी लोक सेवकों को पदोन्नति की जगह पदनाम देने के लिए गठित उच्च पदभार समिति में शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा। सरकार समर्थित शिक्षक संघ को इस कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने इस प्रकार का दृढ़ विश्वास दिलाया है। शिक्षक संघ के महामंत्री छात्रवृत्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन एवं उच्च पदभार नीति समिति के सचिव विनोद कुमार ने गुरुवार को मंत्रालय में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि उच्च पद भार नीति में हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। उन्होंने बताया कि लगातार तीन दिनों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रालय में 3 दिन पहले सीएम के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से मिलकर पदनाम की बहुप्रतीक्षित मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा करके ज्ञापन सौंपा गया था। उसके अगले ही दिन प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव से मुलाकात की गई। वे उच्च पदभार समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे मिलकर पत्र सौंपकर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इस समिति के सचिव विनोद कुमार से मिले और समस्या बताएं फिर तत्काल मंत्रालय पहुंच कर सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्हें गत 15 वर्षों की लंबित मांग सहायक शिक्षक, शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति पदनाम के बारे में अवगत करवाया ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि मुझे पीएस सीएम से भी कहा गया है शिक्षक साथियों विश्वास करो। मप्र शिक्षक संघ के प्रयासों से सफलता मिल सकती है। इस दौरान छत्तरी सिंह राठौर ने अपने साथियों से कहा कि हमें कर्म पर भरोसा है। परिणाम परमात्मा को देना है।

सरकार समर्थित शिक्षक संघ के महामंत्री राठौर को दिया अफसरों ने भरोसा

जल संसाधन अभियंता से मिले इंजीनियर

भोपाल। मप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल से मिला। उनको विभागीय समस्याओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। जिसमें प्रमुख रुप से बीस एवं अट्ठाइस बर्ष बाद समयमान वेतनमान समय पर स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की गई। संगठन में जल संसाधन समिति अध्यक्ष जीपी पाठक ने बताया कि सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई एवं त्वरित हल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में इं जे पी पटेल महामंत्री ए पी सिंह वित्त मंत्री सम्मिलित थे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन पर कोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1998 में किए गए ताजा संशोधन को चुनौती पर केंद्र व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। जवाब 23 फरवरी तक देना होगा। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ. एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा- सरकारी कर्मचारियों व लोकसेवकों का भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाई थी। यह अधिनियम अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन कर नई धारा-17 (ए) जोड़ दी। इसमें प्रविधान कर दिया गया कि लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत पर जांच आरंभ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। उपाध्याय ने इस संशोधन को गैरकानूनी बताते हुए तर्क दिया कि लोकसेवक की परिभाषा मे सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि (विधायक-मंत्री) आते हैं। नए प्रविधान के तहत इनके खिलाफ जांच की अनुमति देने वाला भी सरकारी अधिकारी होगा।

पीपुल भास्कर

चर्चा में ब्रायन एक्टन, सिग्नल एप के को-फाउंडर | क्योंकि वाट्सएप की नई शर्तों पर हुए विवाद से इन्हें फायदा हुआ, वाट्सएप का प्रतिस्पर्धी सिग्नल डाउनलोडिंग में नंबर 1 बना

ब्रायन एक्टनः पहले वाट्सएप बनाया, अब उसके ही खिलाफ सिग्नल को खड़ा किया

जन्म- 17 फरवरी 1972 (मिशीगन, अमेरिका)

शिक्षा- बैचलर ऑफ साइंस, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी

पत्नी- टेगन एक्टन

कुल संपत्ति- 18 हजार करोड़ रुपए (फोर्ब्स के अनुसार)

49 साल के ब्रायन एक्टन, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं हैं। बात 2009 की है, जब फेसबुक में इंटरव्यू के लिए गए एक्टन को कंपनी ने नहीं चुना था। लेकिन महज 5 साल बाद ही फेसबुक ने एक्टन और जॉन कूम के बनाए वाट्सएप को 1.3 लाख करोड़ रुपए (19 बिलियन डॉलर) में खरीद लिया। कभी फेसबुक में बतौर कर्मचारी रिजेक्ट हुए एक्टन इस डील से 27 हजार करोड़ रुपए (3.8 बिलियन डॉलर) संपत्ति के मालिक बन गए। डील के बाद भी एक्टन फेसबुक में काम करते रहे, लेकिन 3 साल बाद 2017 में विज्ञापन और निजता के मुद्दे पर उनकी फेसबुक से ठन गई। कंपनी छोड़ने के बाद मार्च 2018 में एक्टन ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि अब फेसबुक डिलीट करने का समय आ गया है। इससे फेसबुक की छवि को नुकसान हुआ। अब दो साल बाद फिर इत्तेफाक है कि वाट्सएप की नई शर्तों से निजता उल्लंघन का मुद्दा पूरी दुनिया में गर्माया हुआ है और इस विवाद से सबसे ज्यादा फायदा दो सोशल मीडिया एप सिग्नल और टेलीग्राम को हो रहा है। पिछले हफ्ते सिग्नल, एपल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला एप बन गया। 11 जनवरी को 13 लाख लोगों ने सिग्नल डाउनलोड किया। सिग्नल के चर्चा में आने के बाद लोग ब्रायन एक्टन के बारे में जानना चाह रहे हैं।

वाट्सएप से मशहूर हुए, 18 हजार करोड़ रुपए के मालिक

कभी ट्विटर-फेसबुक ने इन्हें नौकरी पर नहीं रखा था

एक्टन के याहू में नौकरी शुरू करने के साल भर बाद जॉन कूम ने याहू में नौकरी शुरू की। दोनों ने 2007 में एक साथ नौकरी छोड़ी और दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। इस बीच उन्होंने काम से इतर खेल-कूद और मस्ती में समय बिताया। 2009 में फेसबुक और ट्विटर ने इन्हें नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया था। इसके बाद एक्टन स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में दिमाग दौड़ाने लगे, तभी उनके दोस्त कूम को एक मैसेजिंग एप्लिकेशन विकसित करने का आइडिया आया। और दोनों ने साथ में मिलकर 2009 में ही वाट्सएप लॉन्च कर दिया। इससे एक्टन को कंपनी के 20 फीसदी शेयर मिले।

उद्यमियों के परिवार से हैं एक्टन, याहू के 44वें कर्मचारी थे

एक्टन ने कॅरिअर की शुरुआत 1992 में एयरक्राफ्ट से जुड़ी कंपनी रॉकवैल इंटरनेशनल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की। इसके बाद एपल-एडोबी में प्रोडक्ट टेस्टर रहे। 1996 में याहू के शुरुआती दौर में एक्टन कंपनी के 44वें कर्मचारी थे। 2007 तक याहू में उन्होंने विज्ञापन समेत कई विभाग संभाले। एक्टन बताते हैं कि उद्यमिता के बीज उनमें बचपन से ही मौजूद थे। मिशीगन में पले-बढ़े एक्टन की मां ने उड्डयन से जुड़ी हुई कंपनी शुरू की थी। उनकी दादी ने मिशीगन में गोल्फ कोर्स शुरू किया था।

अमीरों की सूची में 1219वें नंबर पर, आधी संपत्ति दान कर चुके

फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ सूची के हिसाब से 18 हजार करोड़ रुपए (2.5 बिलियन डॉलर) संपत्ति के साथ एक्टन दुनिया के 1219 वें सबसे अमीर शख्स हैं। एक्टन 2014 से चैरिटी कर रहे हैं। पत्नी टेगन के साथ मिलकर उन्होंने वाइल्डकार्ड गिविंग नाम की चैरिटी संस्था बनाई है। इसके जरिए उन्होंने अब तक 7 हजार करोड़ रु. से ज्यादा की संपत्ति विभिन्न सामाजिक कामों के लिए दान की है। वह सनलाइट गिविंग फाउंडेशन के जरिए सैन फ्रांसिस्को में कमजोर आय वर्ग के लोगों की मदद कर रहे हैं।

प्राइवेसी पर फेसबुक से खटास हुई, सिग्नल आजीवन मुफ्त रखने पर जोर

एक्टन बताते हैं कि जुकरबर्ग ने वाट्सएप का व्यावसायिक रूप से फायदा उठाने के लिए उन पर दबाव बनाया। विज्ञापन और मैसेजिंग को व्यावसायिक अनुकूल बनाने एनक्रिप्शन करने को कहा। एक्टन जोर दे रहे थे कि उपयोगर्ताओं की संख्या से कंपनी पैसा कमा सकती है, एक्टन के अनुसार फेसबुक विज्ञापन पर जोर दे रही थी। इस विरोध की एक्टन को कीमत भी चुकानी पड़ी। अपने हिस्से के स्टॉक मिलने की समय सीमा से एक साल पहले ही उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया। इससे उन्हें 6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2014 में मॉक्सी मार्लिनस्पाइक ने सिग्नल एप विकसित किया। 2017 में एक्टन ने सिग्नल एप में 50 मिलियन डॉलर का निवेश किया। 2018 में सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की। एक्टन के मुताबिक सिग्नल सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस है और वे इसका इस्तेमाल व्यापारिक हित के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे।

कॉलेज खोलने को लेकर 18 को होगी तैयारियों पर चर्चा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के कॉलेजों में 20 जनवरी से नियमित कक्षाएं शुरू करने के पहले उच्च शिक्षा विभाग 18 जनवरी को विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज प्राचार्यों के साथ तैयारियों की ऑनलाइन समीक्षा करेगा। बैठक में 10 जनवरी से शुरू की गई अंतिम वर्ष की कक्षाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। 20 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कॉलेजों में शुरू होगी, इसलिए विभागीय स्तर पर कैलेंडर पर मंथन किया जाएगा। बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी जिसमें 14 बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसके बाद कोर्ट पेंडेंसी, लोकार्पण, शिलान्यास के निर्माण कार्यों की जानकारी, पद और विषयों को मर्ज करने की कवायद, परीक्षा पर चर्चा, छात्रवृत्ति सहित कई अहम विषयों पर मंथन किया जाएगा।

स्वास्थ्य प्रोग्राम के लिए शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण

भोपाल। सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें बच्चों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी से शिक्षकों को ऑनलाइन चार दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी के शिक्षकों को शामिल किया गया है। 18 जनवरी से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के 5942, हाईस्कूल के 2204 और हायर सेकंडरी के 1720 शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 500 रुपये इंटरनेट के लिए और 700 रुपये प्रतिदिन के मान से मानदेय भी दिया जाएगा।

लोकसेवक की जाँच के पहले अनुमति लिए जाने के प्रावधान को कोर्ट में चुनौती

केन्द्र एवं राज्य सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 23 फरवरी को

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

मप्र हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर लोकसेवक की जाँच के पहले अनुमति लिए जाने के प्रावधान जोड़ने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को नियत की गई है।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया था। 2 जुलाई 2018 को इस अधिनियम में संशोधन कर नई धारा 17 ए जोड़ दी गई, जिसके तहत अब लोकसेवकों की जाँच के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

याचिका में कहा गया है कि लोकसेवकों की परिभाषा में सरकारी अधिकारियों के साथ नेता भी आते हैं। जाँच की अनुमति के लिए सरकारी अधिकारियों के पास जाना होगा। सरकारी अधिकारी और नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जाँच की अनुमति नहीं देने देंगे। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि लोकसेवकों के खिलाफ जाँच के पूर्व अनुमति लिए जाने का प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। इस प्रावधान का फायदा भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को होगा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पी-4

पंचायतों में मनरेगा मतलब मनमर्जी योजना

बेवजह तबादलों के नाम पर किया जा रहा अभियंताओं को परेशान, नोटिस के माध्यम से लगती है पेशी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

जन कल्याण के लिए भारत सरकार की संचालित मनरेगा योजना मैदानी अधिकारियों के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं बनी हुई है। इस काम में लगी मैदानी मशीनरी का आरोप है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबरदस्त तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं। बदले की भावना से तबादले किए जा रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

इंजीनियरों के मुताबिक इस योजना का मूल स्वरूप जरूरतमंद एवं जिसको आवश्यकता हो जो मांग करें ऐसे जॉब कार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन कोरोना आने के बाद इस योजना का स्वरूप ही बदल गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है ।

कोरोना काल में जहां सभी विभागों के कार्यालयों में ताले लगे थे वही ग्रामीण विकास अभियंताओं एवं ग्राम रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों सहित नरेगा में में कार्यरत अमले ने कोरोनाकाल में अपनी जान की परवाह न करते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया। जिस कारण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है। वर्तमान में तो जबरन दवाब बनाकर रोजगार दिवस सृजन कराए जा रहे हैं। अब यह हो रहा है कि प्रतिदिन आपको निश्चित लेबर लगाना ही है। इतने लेबर लगाने के निर्देश दिए जाते हैं भले ही लेबर कार्य एवं रोजगार की मांग करें या ना करें। अथवा वास्तविक रूप से इतनी लेबर गांव में उपस्थित ना हो, अन्य जगह विस्थापित हो। तब भी आपको लक्ष्य के अनुसार लेबर प्रदर्शित करना ही है। राशि खर्च करना ही है, ऐसे निर्देश अधिकारियों द्वारा मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं को प्रतिदिन दिए जा रहे हैं।

वेतन राजसात करने की कार्रवाई

इंजीनियरों का आरोप है कि मनरेगा की प्रगति को ही आधार मानकर उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के वेतन राजसात करने की कार्यवाही कई जिलों में की जा रही है जबकि यह लोग मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के कार्य कर रहे हैं। अगर मनरेगा के कार्य को ही प्रगति और वेतन का आधार बनाना है तो फिर मनरेगा से अतिरिक्त अन्य कार्य अन्य कर्मचारियों से करवाना चाहिए ये कार्य उपयंत्री और सहायक यंत्री पर क्यों थोपे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सप्ताह में तीन,चार दिन एक भी जनपद एक भी जिले में बैठक रखी जाती है। जिनमें पूरा दिन खराब होता है और प्रगति बाधित होती है। आरोप यह भी है कि लेबर बजट पूरा करने के नाम पर अत्यधिक मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है।

धमकाया जा रहा है अभियंताओं को

यह भी आरोप है कि प्रतिदिन अभियंताओं को डरा धमका कर लेबर लगाने का दबाव बनाया जाता है,जबकि जॉब चार्ट के अनुसार लेबर लगाने का कार्य उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री का नहीं है। इस दबाव के कारण प्रदेश के ग्रामीण विकास अभियंताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। अनावश्यक रूप से उपयंत्री सहायक यंत्री रोजगार सहायक सचिव जो दिन रात इन कार्यों में प्रगति लाते हैं उनका वेतन काटा जाता है।

अभियंताओं के नियम विरुद्ध कर देते स्थानांतरण

जिला स्तर पर जब जिस अधिकारी का मन होता है एक जनपद से दूसरे जनपद में अभियंताओं के स्थानांतरण किए जाते रहते हैं, जबकि शासन की स्थानांतरण नीति में भी स्पष्ट है कि जिले के जिले में भी यदि स्थानांतरण करना है तो वर्ष में एक बार किया जा सकेगा। वह भी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात यह संभव है, लेकिन यहां कोई किसी भी प्रकार के नियम मानने को तैयार नहीं है। जब तक अभियंता उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझता है, तब तक दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाता है। अभियंताओं का कहना है कि ऐसे में कैसे प्रगति आएगी ये विचारणीय प्रश्न है।

अभियंताओं को मिल रही है नोटिस: मनरेगा का कार्य करवाने में इंजीनियरों को अनावश्यक रूप से बार-बार जिला पंचायतों में नोटिस के माध्यम से बुलाया जा रहा है। जिसको पेशी का नाम दिया जाता है। उन्हें व्हाटसअप ग्रुप पर पेशी के नाम से तलब किया जाता है, पेशी शब्द का प्रयोग आरोपियों के लिए किया जाता है, ये शब्द असम्मानजनक है। आरोप है कि कार्यालय में बुलाकर अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है। मानसिक प्रताड़ना एवं कार्य की अधिकता इतनी है कि अभियंता गण अपनी नौकरी बचाने की वजह से रात को रात को 9 -10 बजे तक कार्य करने को मजबूर है। बात-बात पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभियंताओं की संविदा समाप्त करने वेतन रोकने में निलंबित करने की धमकी दी जाती है। सप्ताह में 1 दिन का भी अवकाश नहीं दिया जाता है छुट्टी के दिन भी अधिकारीगण मीटिंग लेते हैं ड्यूटी लगाई जाती है महिला अभियंताओं से भी असभ्यता पूर्वक व्यवहार किया जाता है।

इंजीनियरों ने दी सड़कों पर उतरने की धमकी: उपरोक्त समस्त परिस्थितियों से क्षुब्ध एवं दुखी होकर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास अभियंता संघ के प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ उप प्रान्त अध्यक्ष सतीश समेले, संयुक्त सचिव सुधिया दुआरे एवं संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इन समस्त विषयों, प्रताड़ना, दवाबों के विषय में शीघ्र समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास अभियंता संघ का प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मप्र रोजगार गारंटी परिषद के समक्ष सभी विषयों को रखेगा। इस दौरान निराकरण के लिए अनुरोध किया जाएगा। निराकरण न होने की स्थिति में पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास अभियंताओं द्वारा सभी तरह के कार्य बंद करने की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा, उन्होंने कहा है कि मनरेगा में संविदा इंजीनियरों के नियमितीकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे, यह पक्ष भी अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।

बोर्ड परीक्षा के पहले माशिमं ने बंद की हेल्पलाइन, स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ी

कोरोना कॉल में हेल्पलाइन पर रोजाना आ रहे थे 900 से 1000 कॉल

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

एमपी बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन ठीक परीक्षा के पहले बंद कर दी गई है। अहम बात यह है कि अच्छे रिस्पॉन्स के कारण इस हेल्पलाइन को पूरे साल चलाया गया। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।

एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चार माह बाद शुरू होंगी। इससे पहले हेल्पलाइन बंद करने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। हर साल मंडल की इस हेल्पलाइन में बोर्ड परीक्षा को लेकर रोजाना 600 से 700 स्टूडेंट्स के कॉल आते थे। कोरोना काल में हर दिन 900 से 1000 तक कॉल आए। इस तरह पिछले वर्ष प्रदेश भर से लगभग 9.38 लाख स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स ने कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान किया।

शिक्षक फोन पर करते थे डाउट क्लीयर: इस हेल्पलाइन से विषय के शिक्षकों को जोड़ा जाता था। हेल्पलाइन नं. 18002330175 पर फोन करने वाले छात्रों को विषय संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए काउंसलर संबंधित विषय के शिक्षक का नंबर देती थीं। इस पर शिक्षकों से बात कर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लीयर करते थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार रेगुलर कक्षाएं नहीं लगी हैं, ऐसे में शिक्षकों के अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता है, तब हेल्पलाइन बंद कर दी गई है।

माध्यामिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में तीन शिफ्ट में 18 काउंसलर और 100 से अधिक विषय विशेषज्ञ शामिल होते थे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक हेल्पलाइन सेवा जारी रहती थी। हर शिफ्ट में 6-6 काउंसलर बच्चों समस्याएं सुनते थे।

विद्यार्थी यहां पा सकते हैं समाधान
वैकल्पिक हेल्पलाइन
उमंग 14425

क्यों जरूरी है हेल्पलाइन

1 कोरोना काल के चलते इस बार कक्षाएं नहीं लगने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई है।
2 मंडल ने 10वी और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए हैं।
3 टाइम टेबल में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दी जाती।
4 कोरोना के कारण परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। नए सेंटर ढूंढने में हेल्पलाइन से मदद मिलती।
5 परीक्षा से पहले काउंसलर से मार्ग दर्शन की जरूरत।

कमेटी के सुझाव पर सरकार ने शुरू की थी हेल्पलाइन

पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा के तनाव और रिजल्ट खराब होने के चलते स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे थे। इस पर रोक लगाने और स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी के सुझाव और विद्यार्थियों के अच्छे रिस्पॉन्स के कारण बीते साल हेल्पलाइन को साल भर चलाया गया, अन्यथा पहले यह पांच माह चलती थी।

Published in 16 Jan-2021 print edition of Raj Express

जनजाति क्षेत्रीय आवासीय विद्यालयों में मॉक टेस्ट शुरू

जयपुर, (ब्यूरो)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 36 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वी एवं 10वी के सभी विषयों में विद्यार्थियों हेतु मॉक टेस्ट शुक्रवार से प्रारंभ हुए है। यह आदेश विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल द्वारा जारी किए गए।

स्कूलों में कोविड19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि इस मॉक टेस्ट की विस्तृत कार्य योजना सीईओ, पदेन माडा परियोजना अधिकारी एवं उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजी जा चुकी है, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षार्थियों के लिए सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी।

आवासीय व्यवस्था में प्रत्येक कक्ष में एक या दो विद्यार्थियों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश है। इसी गाइडलाइन की पालना में परीक्षा कक्ष में बैठक की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को समूह में एकत्र नहीं होने के निर्देश दिए गए है व साथ ही हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है जिससे वे बार-बार हाथ धो सकेंगे। उन्होंने बताया कि टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों, वार्डन एवं कर्मियों को भी इस संबध में पृथक से निर्देश दिए गए है। जो विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर थे उनको सैनिटाइज किया गया है।

प्री बोर्ड: फाइनल की तैयारी परखने का जरिया

कहीं छमाही परीक्षाएँ हो रही हैं, तो कहीं प्री-बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जारी... अलग-अलग स्कूलों में प्री-बोर्ड की अलग डेट, जनवरी के थर्ड वीक और फरवरी में हो सकती हैं परीक्षाएँ

सिटी रिपोर्टर• जबलपुर

बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जारी है। कहीं सिलेबस कम्प्लीट होकर रिवीजन वर्क चल रहा है, तो कहीं सिलबेस अनकम्प्लीट है। इसी बीच एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थी छमाही परीक्षा में व्यस्त हैं। वहीं सीबीएसई, आईसीएसई के विद्यार्थी भी प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। आज हमने विद्यार्थियों से उनकी स्टडी के बारे में जाना, तो कुछ ने कहा कि प्री-बोर्ड जनवरी में होना है तो किसी ने फरवरी सेकेंड वीक में होने की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने बताया कि प्री-बोर्ड एक फाइनल एग्जाम डेमो ही होता है, जिससे काफी कुछ पता चल जाता है। पैटर्न से लेकर मेंटली भी हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों पूरा फोकस स्टडी पर ही हो रहा है। स्टूडेंट्स रोज 6 से 8 घंटे स्टडी करते हैं और ब्रेक लेते हुए ड्रॉइंग, डांस या फिर म्यूजिक सुनकर अपने माइंड को रिलेक्स करना पसंद करते हैं। (आर-1)

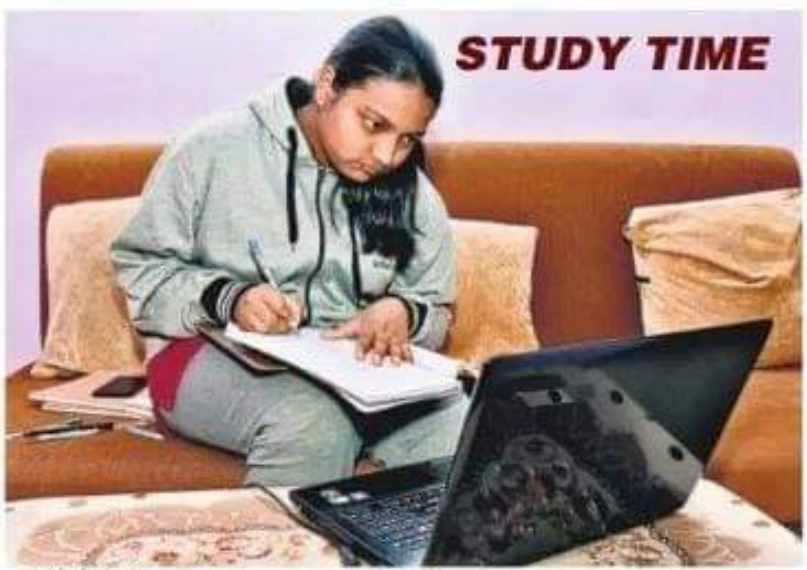

जारी है तैयारी : घर पर ऑनलाइन स्टडी करती स्टूडेन्ट कृतिका।

राइटिंग वर्क की प्रैक्टिस भी जरूरी

प्री-बोर्ड स्कूल लेवल पर आयोजित किया जाता है। इसके लिए कुछ स्कूल्स में प्लानिंग की जा रही है तो कुछ ने डिसाइड कर लिया। प्रैक्टिकल एग्जाम भी जरूरी हैं,इसलिए सारी रूप रेखा प्री-बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम को देखकर तय की जा रही है। यह कहना है सीबीएसई के सिटी-कोऑर्डिनेटर राजेश चंदेल का। उन्होंने कहा कि स्कूलों में क्रेश कोर्स भी चलाएँ जा रहे हैं,ताकि सिलेबस कम्पलीट कराएँ जा सके। स्कूल में क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते थे, जो कि इस बार नहीं हुए। इससे बच्चों की स्टडी में फर्क देखा जा सकता है। ऑनलाइन स्टडी से बच्चों के राइटिंग वर्क में भी असर देखने को मिल रहा है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें।

कुछ ऐसी है बच्चों की प्रिपरेशन

- स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं।
- 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का टारगेट बना रहे हैं।
- प्री-बोर्ड होने से पैटर्न समझ जाएँगे, इसलिए फाइनल एग्जाम की तैयारी हो रही है।
- कुछ स्कूलों में जनवरी के सेकेंड वीक से प्री-बोर्ड स्टार्ट होने हैं, तो कुछ स्कूलों में फरवरी के सेकेंड वीक में। एमपी बोर्ड में अभी छमाही परीक्षाएँ चल रही हैं।
- सिलेबस पूरा होते ही कुछ विद्यार्थी रिवीजन वर्क करते दिख रहे हैं।
- स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आर्ट एण्ड क्राफ्ट का भी सहारा ले रहे हैं।पी-2

सिलेबस कम्प्लीट है, रिवीजन चल रहा

प्री-बोर्ड एग्जाम फरवरी सेकेंड वीक से होंगे। प्री-बोर्ड में हमें पता चलता है कि फाइनल एग्जाम कैसा होगा। किस तरह के पैटर्न से परीक्षाएँ दी जाती हैं। सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है अब रिवीजन चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग 9 घंटे पढ़ाई कर सकूँ। इस बीच माइंड रिलेक्स करने के लिए ड्रॉइंग वर्क कर लेती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है।
कनिका कुमारी, कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड

बोर्ड एग्जाम पर फोकस

मुझे पढ़ना पसंद है, ज्यादा टाइम स्टडी में बीतता है। मेरा पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पर है। मेरा पीसीएम विषय है। डेली सुबह 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, जेईई मेन्स की प्रिपरेशन भी चल रही है। लेट नाइट स्टडी करता हूँ, सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं दिन में सो जाता हूँ। फरवरी सेकेंड वीक में प्री-बोर्ड एग्जाम होंगे।
अर्श जैन, कक्षा 12वीं आईसीएसई बोर्ड

छमाही परीक्षा चल रही

बोर्ड परीक्षा है तो थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कैसे पढ़ाई करनी है, पैटर्न क्या होगा, अब कोरोना की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिलहाल अभी छमाही परीक्षाएँ चल रही है, प्री-बोर्ड एग्जाम की डेट नहीं आई है। मैं डेली 2 घंटे पढ़ रही हूँ अभी परीक्षा है तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है। घर से ही परीक्षाएँ दे रही हूँ।
कृतिका गुप्ता, कक्षा 10वीं एमपीबोर्ड

परिचर्चा

कई स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ा रहे हैं, साथ ही उनके शारीरिक विकास के लिए भी गतिविधियां हों-

पढ़ाई के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी

बच्चों का शारीरिक विकास भी हो

एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलना-कूदना भी जरूरी है। ऑनलाइन क्लॉस के बाद बच्चों को इतना होमवर्क और असाइनमेंट मिल जाता है कि उनका अधिकतर समय उसे पूरा करने में बीत रहा है। इसके बाद खेलने-कूदने का समय ही नहीं बचता है। टीचर पढ़ाने के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करवाएं ताकि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो।

-राजेश कनौजिया, सेवानिवृत्त अधिकारी

क्रिएटिव एक्टिविटी-एंटरटेनमेंट हो

फिलहाल स्कूल भले ही खुल गए हैं, फिर भी ऑनलाइन क्लास और होमवर्क के कारण बच्चे ज्यादा समय मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। पढ़ाई-परीक्षा का मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के साथ बच्चों की खेल गतिविधियां लगभग बंद हो गई हैं। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान एक पीरियड ऐसा हो, जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटी, डिस्कशन, एंटरटेनमेंट शामिल हो। इस तरह बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे।

-विकास गुप्ता, सीनियर ऑफिसर, बीमा कंपनी

अभिभावकों की बढ़ गई जिम्मेदारी

आजकल कुछ स्कूल खुल गए हैं फिर भी अधिकांश स्कूल ऑनलाइन ही पढ़ाई करवा रहे हैं। संक्रमण के वर्तमान हालात को देखते हुए यह कुछ हद तक सही भी है। ऐसे में बच्चों की फिटनेस का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पैरेंट्स की बढ़ गई है। वे यह देखें कि बच्चा पढ़ाई के बाद अनावश्यक रूप से मोबाइल का इस्तेमाल न करे। वह बाहर खेलने जाने के बजाय योगा, साइकिलिंग, रस्सीकूद आदि चीजे करें। इन एक्सरसाइज से वह मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा।

-डॉ. रविन्द्र खाड़े, चिकित्सक

अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल के अलावा घर पर भी बच्चों की खेल गतिविधियां बंद हैं। ऐसे में कई बच्चे बीमार होने लगे हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चे घर पर ही रहकर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। इससे मेंटल स्ट्रेस कम होने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई से होने वाली थकान भी दूर होगी। लेकिन इसका ध्यान बच्चों से ज्यादा पैरेंट्स को रखना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी भी है।

-भावना अवसरकर, हाउसवाइफ

आज का इतिहास

दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुईं कल्पना चावला

16 जनवरी की तारीख भारत की एक बेटी की बड़ी उपलब्धि की साक्षी है, जिसने अमेरिका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने को पूरा किया और एक बार नहीं बल्कि उन्हें 2 बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। बता दें कि कल्पना चावला ने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भरी थी। हालांकि उनकी यह उड़ान अंतिम साबित हुई। क्योंकि 16 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते हुए 1 फरवरी को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक दल के 6 सदस्यों के साथ उनकी भी मौत हो गई।

16 जनवरी की प्रमुख घटनाएं

1556- फिलिप द्वितीय स्पेन के सम्राट बने।

1581- ब्रिटिश संसद ने रोमन कैथोलिक मत को गैर कानूनी घोषित किया।

1681- शिवाजी के पुत्र संभाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ।

1769- पहली संगठित घुड़दौड़ कलकत्ता के निकट अकरा में आयोजित की गई।

1938 - बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन।

1992 - भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि।

आज का इतिहास

- **1556:** स्पेन के सम्राट कैरेल ने पुत्र फिलीप द्वितीय को उत्तराधिकारी चुना।
- **1581:** ब्रिटिश संसद ने रोमन कैथलिकों के खिलाफ कानून बनाया।
- **1681:** छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ।
- **1769:** कलकत्ता के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ आयोजित।
- **1901:** प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक महादेव रानाडे का निधन।
- **1938:** प्रख्यात बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन।
- **1943:** इंडोनेशिया के अंबोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हमला।
- **1947:** विंसेंट ऑरियल फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गये।
- **1955:** पुणे में खड्गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उद्घाटन।
- **1966:** शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी साधु वासवानी का निधन।

आज का इतिहास

1926 ओ. पी. नैय्यर- प्रसिद्ध संगीतकार का जन्म हुआ।

1630 गुरु हरराय - सिक्खों के सातवें गुरु का जन्म हुआ।

1901 महादेव गोविन्द रानाडे - भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद का निधन हुआ।

1938 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय- बांग्ला भाषा के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार का निधन हुआ।

1992 भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई।

1996 हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नई आकाशगंगा को खोज निकालने का दावा किया।